Model Answer

Que. Discuss whether the formation of new states in recent times is beneficial or not for the economy of India.

State formation in India has been a crucial aspect of its political history, particularly in the post-independence era. Historically, new states have been created to address regional disparities, cultural and linguistic differences, and governance inefficiencies. Key examples include the creation of **Uttarakhand (2000)**, **Jharkhand (2000)**, and **Telangana (2014)**.

Arguments in Favor of New State Formation:

- Localized Governance: Smaller states enable more focused governance and faster implementation of policies. Jharkhand, formed from Bihar, for instance, has been able to focus more on its vast mineral resources and industrial growth.
- Balanced Development: States like Telangana have benefitted from the creation of dedicated policies for agriculture, industry, and IT, resulting in strong economic growth in the region.

Arguments Against New State Formation:

- Initial Economic Disruptions: The bifurcation of Andhra Pradesh in 2014 led to a loss of its economic capital, Hyderabad, which affected revenue generation for the newly formed state.
- High Administrative Costs: The process of creating new capitals and administrative structures leads to significant initial expenditure. For instance, Telangana had to invest heavily in building infrastructure, including a new capital city, Amaravati, in Andhra Pradesh.

Successes and Failures:

- Successes: Uttarakhand and Chhattisgarh experienced faster development in sectors like tourism, agriculture, and industrialization post-formation.
- Failures: Some states like Bihar post-creation of Jharkhand and Andhra Pradesh post-formation of Telangana have faced economic strain due to redistribution of resources and revenue generation challenges**.**

Need for Planning:

Proper planning, resource allocation, and infrastructure development are key to the success of new states. The formation of states should be accompanied by strategies to ensure equal distribution of resources and balanced development, with clear focus on education, health, and industry.

While the formation of new states has led to focused regional development and governance, it brings challenges such as economic strain in the short term and high administrative costs. The success of such formations relies on proper strategic planning and resource management. Hence, a balanced approach is essential to ensure the long-term benefits of new state formations for India's economy.

प्रश्नः चर्चा कीजिए कि क्या हाल के समय में नए राज्यों का गठन भारत की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है या नहीं।

भारत में, खास तौर पर स्वतंत्रता के बाद, राज्यों का गठन उनके राजनीतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। ऐतिहासिक रूप से, क्षेत्रीय असमानताओं, सांस्कृतिक और भाषाई मतभेदों और शासन की अक्षमताओं को दूर करने के लिए नए राज्यों का गठन किया गया। प्रमुख उदाहरणों में उत्तराखंड (2000), झारखंड (2000) और तेलंगाना (2014) का गठन शामिल है।

नए राज्यों के गठन के पक्ष में तर्कः

- ***स्थानीय शासनः*** *छोटे राज्य अधिक केंद्रित शासन और नीतियों के तेज़ क्रियान्वयन को सक्षम बनाते हैं। उदाहरण के लिए, बिहार से निर्मित झारखंड अपने खनिज संसाधनों और औद्योगिक विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में सक्षम रहा है।*
- ***संतुलित विकासः*** *तेलंगाना जैसे राज्यों को कृषि, उद्योग और आईटी के लिए समर्पित नीतियों के निर्माण से लाभ हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्र का आर्थिक विकास हुआ है।*

नए राज्यों के गठन के खिलाफ तर्कः

- ***प्रारंभिक आर्थिक व्यवधानः*** *2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के कारण इसकी आर्थिक राजधानी हैदराबाद का नुकसान हुआ, जिससे नवगठित राज्य का राजस्व सृजन प्रभावित हुआ।*
- ***उच्च प्रशासनिक लागतः*** *नई राजधानियाँ और प्रशासनिक संरचनाएँ बनाने की प्रक्रिया में अधिक प्रारंभिक व्यय होता है। उदाहरण के लिए, तेलंगाना को आंध्र प्रदेश में एक नई राजधानी अमरावती सहित बुनियादी ढाँचे के निर्माण में भारी निवेश करना पड़ा।*

सफलताएँ और असफलताएँः

- ***सफलताएँः*** *उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ ने पर्यटन, कृषि और औद्योगिकीकरण जैसे क्षेत्रों में गठन के बाद तेजी से विकास का अनुभव किया।*
- ***असफलताएँः*** *झारखंड के गठन के बाद बिहार एवं तेलंगाना के गठन के बाद आंध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्यों को संसाधनों के पुनर्वितरण और राजस्व सृजन संबंधी चुनौतियों के कारण आर्थिक तनाव का सामना करना पड़ा।*

नियोजन की आवश्यकताः

नए राज्यों की सफलता के लिए उचित नियोजन, संसाधन आवंटन और बुनियादी ढांचे का विकास महत्वपूर्ण है। राज्यों के गठन के साथ संसाधनों के समान वितरण और संतुलित विकास को सुनिश्चित करने की रणनीति भी होनी चाहिए, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

नए राज्यों के गठन से क्षेत्रीय विकास और शासन पर ध्यान केंद्रित हुआ है, लेकिन इससे अल्पावधि में आर्थिक तनाव और उच्च प्रशासनिक लागत जैसी चुनौतियाँ भी आई हैं। ऐसे गठन की सफलता उचित रणनीतिक नियोजन और संसाधन प्रबंधन पर निर्भर करती है। इसलिए, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए नए राज्यों के गठन के दीर्घकालिक लाभों को सुनिश्चित करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है।